

मुकदमों का विवरण

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना

वी.

मेसर्स शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

(2023 का सिविल अपील सं. 3991 आदि) 13 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या शैक्षणिक संस्थान-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला मेगा सेवा कर छूट अधिसूचना में "सरकारी प्राधिकरण" की अवहेलना के दायरे में आते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ सरकार, सरकारी या स्थानीय अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली कर प्रणाली से विभिन्न सेवाओं को छूट देते हैं।

कर/कराधान-सेवा कर-शैक्षणिक संस्थानों-आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला से छूट यदि **20 जून, 2012** की मेगा सेवा कर छूट अधिसूचना संख्या **25/2012**, जी. एस. आर. **467 (ई)** में 'सरकारी प्राधिकरण' की अवज्ञा के दायरे में आती है, जिसमें विभिन्न सेवाओं को सेवा कर से छूट दी गई है:

आयोजित किया गया: शैक्षणिक संस्थान-आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला खंड 2 (ओं) के तहत 'सरकारी प्राधिकरण' की संशोधित अवज्ञा के तहत आते हैं और शैक्षणिक संस्थानों को छूट अधिसूचना में लाभ के लिए पात्र हैं और सेवा कर से मुक्त हैं-स्पष्टीकरण अधिसूचना के माध्यम से खंड 2 (ओं) में 'सरकारी प्राधिकरण' की संशोधित परिभाषा ने संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय को भी प्रदान किए जाने वाले सेवा कर के लिए छूट आधार को चौड़ा कर दिया है, बिना इस शर्त के कि सरकार द्वारा 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किया गया है।

421

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“सरकारी प्राधिकरण” खंड को पहले की अवज्ञा के विपरीत व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से-पटना उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णयों ने शैक्षणिक संस्थानों को छूट अधिसूचना का लाभ उचित रूप से दिया है, और एस. पी. सी. एल. को एक अधिकार दिया गया है-इस प्रकार, विवादित निर्णयों और आदेशों को बरकरार रखा गया है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। [पैरा 30,34]

सर्कुलर/सरकारी आदेश/अधिसूचना-मेगा सेवा कर छूट अधिसूचना-खंड 2 (ओं) (स्पष्टीकरण अधिसूचना द्वारा संशोधित), 'सरकारी प्राधिकरण' की अवहेलना-शब्द की व्याख्या 'या' खंड 2 (ओं) में नियोजित:

आयोजित किया गया:खंड 2 (ओं) में प्रयुक्त शब्द "या" एक विकल्प निर्धारित करने के विधायी इरादे को प्रकट करता है-व्याख्या के सुनहरे नियम के अनुसार कि शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, खंड 2 (ओं) में "या" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से सामान्य और सामान्य अर्थ को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया प्रतीत होता है, जो एक विकल्प देते हुए एक विकल्प को दर्शाता है। और, एक भिन्न अर्थ तब तक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह अस्पष्टता की ओर ले जाता है या खंड 2 (ओं) को पूरी तरह से अव्यवहारिक नहीं बनाता है-शब्द "या" उप-खंडों (i) और (ii) के बीच उप-खंड (i) की स्वतंत्र और असंगत प्रकृति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि "या" उप-खंड (i) के बाद उपयोग किए गए "की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है" और "ताकि इसे खंड 2 (ओं) की लंबी पंक्ति में गणना की गई शर्त के साथ जोड़ा जा सके जो केवल उप-खंड (ii) पर लागू होती है-शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, उप-खंड (i) और (ii) के बीच 'संयोजन' या 'स्पष्ट रूप से दो खंडों को पहले भाग के साथ दो भागों में विभाजित करता है।[पैरा 23,24,28]।

परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचना-वृहद सेवा कर छूट अधिसूचना-खंड 2 (ओं) (स्पष्टीकरण अधिसूचना द्वारा संशोधित)-स्पष्टीकरण अधिसूचना के खंड 2 (ओं) में विराम चिह्न 'सरकारी प्राधिकरण' की अवहेलना-व्याख्या:

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

423

आयोजित किया गया:निर्माण के उद्देश्य के लिए विराम चिह्न का सहारा लिया जा सकता है-अर्धविराम का उपयोग कोई तुच्छ बात नहीं है, बल्कि इसे उपखंड (ii) से अलग करने के स्पष्ट इरादे से जानबूझकर शामिल किया जा सकता है-खंड 2 (ओं) के एक स्पष्ट और शाब्दिक पढ़ने पर कि उपखंड (i) के बाद एक अर्धविराम होता है, उपखंड (ii) अल्पविराम के साथ बंद हो जाता है, यह अनिवार्य रूप से एकमात्र संभावित निर्माण का समर्थन करता है कि उपखंड (ii) के बाद अल्पविराम का उपयोग इसे उसके बाद प्रदान की गई लंबी रेखा से संबंधित करता है और कल्पना के किसी भी विस्तार से, लंबी रेखा के अनुप्रयोग को उपखंड (i) तक बढ़ाया जा सकता है।[पैरा 26,27]

विधियों की व्याख्या-प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या-व्याख्या के नियम:

आयोजित किया गया:स्पष्ट और अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जैसे इसे निर्धारित किया गया है और न कि इस तरह से कि यह प्रावधान की अवहेलना करता है और प्रावधान के अर्थ और संदर्भ को मौलिक रूप से बदल देता है-प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या जिसके परिणामस्वरूप इसके संचालन का दायरा बढ़ जाता है, अपने आप में प्रावधान की अस्पष्टता को जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है-व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग करके एक

क़ानून को व्यवहार्य बनाना और एक प्रकार के न्यायिक विधान में उद्यम करना दो अलग-अलग चीज़ें हैं-केवल इसलिए कि क़ानून इच्छित या वांछित परिणाम नहीं देता है, जो इसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए व्याख्या के उपकरणों का उपयोग करके सीमा को पार करने का कारण नहीं हो सकता है-एक क़ानून को व्यवहार्य बनाने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और न कि।[पैरा 20,32,33]

अधिकतम-शब्दों में उद्धरण अस्पष्टता है, इबी नुल्ला एक्सपोज़िशियो कॉन्ट्रा वर्बा एक्सप्रेसो फाई एंडा एस्ट-इसका अर्थ है:

424

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आयोजित किया गया:जब शब्दों में कोई अस्पष्टता नहीं होती है, तो शब्दों के विपरीत कोई व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।[पैरा 30]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार और

कंपनी और ओआरएस। (2018) 9 एससीसी 1:[2018] 7 एस. सी. आर. 1191-लागू नहीं होता।

बरुण कुमार और अन्य बनामझारखंड राज्य और अन्य। (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1093; बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पुलक उद्यम और अन्य। (2009) 5

एस. सी. सी. 641; ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम एफकॉन्स गुनानुसा जेवी (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1122;

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनामहरियाणा राज्य (2017) 12 एससीसी 1:[2016] 10 एससीआर 1; अक्षैबर लाल (डॉ.) बनाम कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (1961) 3 एससीआर 386; आईटीसी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोलकाता (2019) 17 एससीसी 46:[2019] 13 एस. सी. आर. 357; अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कलकत्ता निगम (1967) 2 एस. सी. आर. 170; भारत संघ और अन्य। वी.इंड-स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (2011) 4 एससीसी 635:[2011] 2 एससीआर 1087; बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाममोदी शुगर मिल्स लिमिटेड (1961) 2 एस. सी. आर. 189; उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी (पी) लिमिटेड बनाम.उड़ीसा राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 279:[1987] 3 एस. सी. आर. 317; ग्रीन बनाम प्रीमियर

ग्लाइनरहॉन्वी स्लेट कंपनी (1928) 1 के. बी. 561, पृष्ठ 56; श्री जयराम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम ए. जी. सैयद मोहिदीन

(2010) 2 एससीसी 513:[2010] 1 एस. सी. आर. 1127; कांतारू राजीवरु बनाम इंडियन यंग वकीलों का संगठन और अन्य। (2020) 9 एस. सी. सी. 121; गिरधारी लाल एंड संस बनाम.

बलबीर नाथ माथुर (1986) 2 एस. सी. सी. 237:[1986] 1 एस. सी. आर. 383-संदर्भित। ग्रीन बनाम। प्रीमियर ग्लाइनरहॉन्वी स्लेट कंपनी (1928) 1 के. बी. 561-संदर्भित। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 3991। 2015 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.16965 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.03.2016 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 3992।

रूप:

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., गोपाल शंकर नारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री निशा बागची, रुपेश कुमार, वीर विक्रान्त सिंह, 425

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस.

सुश्री रुक्मिणी बोबडे, विक्रान्त सिंह, राकेश करेल्ला, जयेश बख्शी, रवि त्यागी, गौरव मिश्रा, चिराग शर्मा, दमन पोपली, सुश्री रिया चंदा, सुश्री नीतू देवरानी, सुश्री साक्षी टिबरेवाल, सुश्री साक्षी झा, सुश्री अदिति गुप्ता, पी. वी. योगेश्वरन, राज बहादुर यादव, श्रीमती अलका अग्रवाल, प्रशांत सिंह द्वितीय, शांतनु शर्मा, सुश्री विभूती मल्होत्रा, भुवनेश सतीजा, उदित शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, जे.

वरीयता

1. हमें दो दीवानी अपीलों पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है जो एक सामान्य प्रश्न पर केंद्रित हैं: (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ("आई. आई. टी. पटना", इसके बाद) और (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला ("एन. आई. टी. राउरकेला", इसके बाद), मेगा सेवा कर छूट अधिसूचना 1 ("छूट अधिसूचना", इसके बाद) में "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा के दायरे में आते हैं या नहीं। यदि छूट अधिसूचना की अवहेलना करते हुए "सरकारी प्राधिकरण" आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला को अपने दायरे में लेता है, तो वे सेवा कर से छूट के लिए पात्र होंगे जो अन्यथा सेवा प्रदाताओं या उप-ठेकेदारों द्वारा उनके परिसर के भीतर प्रदान की जाने वाली निर्माण सेवाओं पर लागू होता है।

अपीलें

2. 2023 की सिविल अपील संख्या 3991 ("सीए-I", इसके बाद) में, अपीलार्थी पटना में उच्च न्यायालय ("पटना उच्च न्यायालय", इसके बाद) के 3 मार्च, 2016 के निर्णय और आदेश पर हमला करता है, जिसके तहत प्रथम प्रतिवादी, यानी मैसर्स शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("एसपीसीएल", इसके बाद) द्वारा दायर एक रिट याचिका 2 को अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी द्वारा एकत्र किए गए सेवा कर को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

1 सं. 25/2012, जी. एस. आर. 467 (ई) दिनांक 20 जून, 2012 2 सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 2015 का 16965

426

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

3. 2023 की सिविल अपील संख्या 3992 ("सीए-II" इसके बाद) कटक ("उड़ीसा उच्च न्यायालय", इसके बाद) में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 05 फरवरी, 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एस. पी. सी. एल. के पक्ष में पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, कानून के एक समान प्रश्न पर, सेवा कर की वापसी के लिए एस. पी. सी. एल. द्वारा पसंद की गई एक रिट याचिका 3 को अनुमति दी।

संबंधित सूचनाएं

4. राजस्व विभाग द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 ("1994 अधिनियम", इसके बाद) की धारा 93 के तहत छूट अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कर योग्य सेवाओं को धारा 66 बी के तहत पूरे सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई थी। छूट अधिसूचना का खंड 12 (सी), जो वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

“12. सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को निर्माण, निर्माण, चालू करने, स्थापना, पूरा करने, फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं -

(ए) * * *

(बी) * * *

(ग) एक संरचना जो मुख्य रूप से (i) एक शैक्षिक, (ii) एक नैदानिक, या (iii) एक कला या सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए है;

(डी) * * *

(ई) * * *

(च) * * * "

5. चूँकि हम "सरकारी प्राधिकरण" की व्याख्या से चिंतित हैं, इसलिए "सरकारी प्राधिकरण" की अवहेलना करने वाली छूट अधिसूचना के खंड 2 (ओं) को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“((ड) "सरकारी प्राधिकरण" से एक बोर्ड, या एक प्राधिकरण या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है जो इक्विटी के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किया गया हो।

3 डब्ल्यू. पी. (ग) 2015 427 की सं. 17188

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 428

या सरकार द्वारा नियंत्रण और संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित।”

6. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 1994 के अधिनियम की धारा 66 डी, जिसे वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी अधिनियम के साथ जोड़ा गया है, सेवाओं की नकारात्मक सूची, यानी उन सेवाओं को निर्दिष्ट करती है जिन पर सेवा कर नहीं लगाया जाता है। 7. छूट अधिसूचना के खंड 2 (ओं) में 30 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से एक संशोधन किया गया ("स्पष्टीकरण अधिसूचना", इसके बाद)। "सरकारी प्राधिकरण" को फिर से परिभाषित करने वाले इस संशोधन ने छूट के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास किया। संशोधित परिभाषा नीचे दी गई है:

“((ड) "सरकारी प्राधिकारी" से कोई प्राधिकारी या बोर्ड या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है;

((i) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित; या (ii) सरकार द्वारा स्थापित,

संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ।”

8. विचाराधीन प्रासंगिक कानूनी ढांचे को रेखांकित करने के बाद, हम पटना उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की उत्पत्ति के तथ्यों पर गहन विचार करना उचित समझते हैं। तथ्य

9. सी. ए.-आई. की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं:

क) चौथे प्रतिवादी, आई. आई. टी. पटना ने अपने शैक्षणिक परिसर के लिए भवन/सुविधाओं/सेवाओं के निर्माण की देखरेख के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में तीसरे प्रतिवादी, एन. बी. सी. सी. इंडिया लिमिटेड ("एन. बी. सी. सी.", इसके बाद) को नियुक्त किया। 20 दिसंबर, 2012 के पुरस्कार पत्र के माध्यम से, एन. बी. सी. सी. ने एस. पी. सी. एल. को कुल अनुबंध मूल्य Rs.167,70,09,043.00 (केवल एक सौ साठ-सात करोड़ सत्तर लाख नौ हजार चालीस-तीन रुपये) पर निर्माण कार्यों का अनुबंध प्रदान किया। खंड 4.2।4 में से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

पुरस्कार पत्र में निर्दिष्ट किया गया था कि उपरोक्त दरों में सेवा कर शामिल नहीं है और एस. पी. सी. एल. को रसीदें प्रदान करने पर आई. आई. टी. पटना द्वारा इस कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख) एस. पी. सी. एल. ने पुरस्कार पत्र के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ("सी. ई. एस. टी.", इसके बाद) के साथ विधिवत खुद को पंजीकृत किया और मार्च 2013 से अप्रैल 2015 तक की अवधि के लिए अपने सेवा कर दायित्वों का निर्वहन किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सेवा कर राशियों को उपरोक्त महीनों के मासिक चालू बिलों में एकीकृत किया गया था, जिन्हें एस. पी. सी. एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बाद में आई. आई. टी. पटना द्वारा अनुमोदित और भुगतान किया गया था। इसका मतलब था कि आई. आई. टी. पटना अंततः सेवा कर बकाया के निपटान के लिए जिम्मेदार था।

ग) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग ने 30 जून, 2015 को इस आशय के अधिनियम पर एक लेखा परीक्षा आपत्ति जताई कि छूट अधिसूचना के खंड 12 (सी) के अनुसार "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" के मानदंडों को पूरा करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्माण गतिविधियों में लगे सेवा प्रदाता सेवा कर भेजने के लिए बाध्य नहीं थे। नतीजतन, क्योंकि आई. आई. टी. पटना को एक सरकारी प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उनके द्वारा सेवा कर के भुगतान पर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि इस तरह के भुगतान ने छूट अधिसूचना में निर्दिष्ट छूट प्रावधान का उल्लंघन किया था। इसके अतिरिक्त, आई. आई. टी. पटना को एस. पी. सी. एल. को पहले भुगतान किए गए सेवा कर की वसूली या समायोजन के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

घ) लेखा परीक्षा आपत्ति की प्राप्ति के बाद, आई. आई. टी. पटना ने 27 अगस्त, 2015 को एक पत्र के माध्यम से एन. बी. सी. सी. को सूचित किया और बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (कर अनुसंधान इकाई) ने सहायक शैक्षिक सेवाओं की अवज्ञा को स्पष्ट कर दिया है। इस स्पष्टीकरण में विभिन्न सेवाओं की गणना शामिल थी जो पात्र शैक्षणिक संस्थान प्राप्त कर सकते थे और जिन्हें सेवा कर से छूट दी जाएगी। विशेष रूप से, इस स्पष्टीकरण में

निर्माण गतिविधि का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आई. आई. टी. पटना ने अपने 429 अंक व्यक्त किए।

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 430

सेवा कर प्रतिपूर्ति की वसूली के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित करने का इरादा।

ई) पहले से भुगतान किए गए सेवा कर के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू होने की आशंका में, एस. पी. सी. एल. ने निम्नलिखित राहत के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया:

“((i) प्रत्यर्थी सं। 2 दिनांक 30.06.2015 (जैसा कि अनुलग्नक-6 में निहित है) प्रत्यर्थी सं. द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए सेवा कर की तत्काल वसूली समायोजन का निर्देश देना। 4 निरस्त किया जाए।

((ii) इस घोषणा के लिए कि [आई. आई. टी. पटना] अपने भवन परिसर के निर्माण की सेवा पर [एस. पी. सी. एल.] द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है।

((iii) वैकल्पिक रूप से [आयुक्त, सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर] को अनुबंध के अनुसरण में [आई. आई. टी. पटना] के भवन परिसर के निर्माण की सेवा पर [एस. पी. सी. एल.] द्वारा भुगतान की गई सेवा कर की राशि को वापस करने के निर्देश के लिए।”

च) विवादित फैसले के दौरान, पटना उच्च न्यायालय ने एस. पी. सी. एल. की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि आई. आई. टी. पटना वास्तव में खंड 2 (ओं) के तहत "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा के दायरे में आएगा। खंड 2 (ओं) की अपनी व्याख्या में, न्यायालय ने कहा कि खंड 2 (ओं) के उपखंड (i) और (ii) में निहित प्रावधान स्वतंत्र असंवैधानिक प्रावधान हैं और "संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए समानता या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी" अभिव्यक्ति उपखंड (ii) से संबंधित है क्योंकि उपखंड (i) के बाद विराम चिह्न "; और फिर संयोजन" या "होता है। न्यायालय के अनुसार, संसद के किसी अधिनियम या उपखंड (i) में परिकल्पित राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण को "इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी" की शर्त के अधीन नहीं बनाया जा सकता है और यह केवल एक प्राधिकरण या बोर्ड या सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निकाय है, जैसा कि खंड 2 (ओं) के उपखंड (ii) के तहत परिकल्पित है, जिसे इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक की सरकारी भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करना है। तदनुसार यह फैसला सुनाया गया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एस. पी. सी. एल. द्वारा की गई निर्माण गतिविधि को स्पष्टीकरण अधिसूचना के साथ पठित छूट अधिसूचना के संदर्भ में सेवा कर के भुगतान से छूट दी गई है, जिसके बाद एक निर्देश दिया जाता है कि राजस्व द्वारा एकत्र किया गया सेवा कर एस. पी. सी. एल. या आई. आई. टी. पटना को वापस कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

10. सीए-II की प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

क) एस. पी. सी. एल. को एन. आई. टी. राउरकेला द्वारा अपने परिसर में निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 22 फरवरी, 2013 के कार्य आदेश के माध्यम से एक कार्य अनुबंध प्रदान किया गया था। अनुबंध का कुल मूल्य Rs.302,82,39,866.00 (केवल तीन सौ दो करोड़ अस्सी लाख उनतीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये) था। कार्य आदेश के खंड 12 में कहा गया है कि उपरोक्त मूल्य में सेवा कर को छोड़कर सभी कर शामिल होंगे जिन्हें लागू होने पर प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

ख) एस. पी. सी. एल. ने एन. आई. टी., राउरकेला को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर के लागू होने के संबंध में सेवा कर आयुक्तालय से स्पष्टीकरण मांगा।

ग) तथापि, एस. पी. सी. एल. ने सेवा कर विभाग को अपनी सेवा कर देनदारी राशि 5,79,17,168.00 (केवल पाँच करोड़ उनतालीस लाख सत्रह हजार एक सौ अड़सठ रुपये) का भुगतान किया और सभी बिलों को एन. आई. टी., राउरकेला से सेवा कर वसूलने के लिए बढ़ा दिया। हालाँकि, एन. आई. टी., राउरकेला द्वारा कोई सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था, यह दावा करते हुए कि निष्पादित कार्य सेवा कर के भुगतान से मुक्त है।

घ) पीड़ित, एस. पी. सी. एल. ने इस तरह के सेवा कर भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

ङ) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश पर भरोसा करते हुए एस. पी. सी. एल. की रिट याचिका को मंजूरी दे दी। सेवा कर उपायुक्त को दो महीने के भीतर सेवा कर की वापसी के लिए एस. पी. सी. एल. के लंबित आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्ता, जे.] 432 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

431

प्रस्तुतियाँ

11. दोनों अपीलों में अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान वकील सुश्री बागची ने तर्क दिया कि आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला छूट अधिसूचना में उल्लिखित लाभों के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि इसे "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा से बाहर रखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए, उन्होंने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

क) स्पष्टीकरण अधिसूचना के माध्यम से की गई छूट अधिसूचना में संशोधन का उद्देश्य वैधानिक निकायों से परे इसकी प्रयोज्यता को व्यापक बनाना और सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं को भी इसका लाभ देना है। स्पष्टीकरण अधिसूचना ने "सरकारी प्राधिकरणों" की अवज्ञा के भीतर सरकार द्वारा स्थापित निकायों को शामिल करके इस विस्तार को और स्पष्ट किया। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 90 प्रतिशत या उससे अधिक सरकारी इक्विटी या नियंत्रण की आवश्यकता अभी भी दोनों प्रकार के सरकारी निकायों पर लागू होती है, चाहे वे वैधानिक हों या गैर-वैधानिक।

ख) उच्च न्यायालय की त्रुटि उपखंडों की स्वतंत्र और असंगत के रूप में अपनी व्याख्या में निहित है। उपखंड (ii) से "90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी" की शर्त को जानबूझकर अलग करना दोनों उपखंडों पर इसे लागू करने के विशिष्ट इरादे को पूरा करता है।

ग) यह निश्चित रूप से स्थापित किया गया है कि केवल विराम चिह्नों को किसी कानून की व्याख्या को निर्देशित नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जब कानून का अर्थ उनके बिना स्पष्ट हो। सामान्य सिद्धांत यह है कि विराम चिह्न कानूनों की व्याख्या में कम महत्व रखते हैं, विशेष रूप से जब अधीनस्थ विधान से संबंधित होते हैं। इसके अलावा, विराम चिह्न अलग-अलग प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं, और उनकी व्याख्या को अलग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विधायी इरादे को समझने के लिए अन्य खंडों के साथ संयोजन में विचार किया जाना चाहिए। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया था

बरुण कुमार और ओआरएस बनाम झारखंड राज्य और अन्य। 4, बिहार राज्य

4 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1093

विद्युत बोर्ड बनाम पुलक उद्यम और अन्य। 5, और ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम एफकोन्स गुनानुसा जे. वी. 6।

घ) विधायी आशय को पूरा करने के लिए 'या' और 'और' शब्दों की एक दूसरे के स्थान पर व्याख्या की जा सकती है। इस संदर्भ में, संदर्भ दिया गया था

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसलों के लिए। हरियाणा राज्य 7, बरुण कुमार (उपरोक्त) और अक्षैबर लाल (डॉ.) बनाम कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 8.

ई) पटना उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे विभिन्न सार्वजनिक निकायों को शामिल करने के लिए छूट के दायरे और दायरे को बिना शर्त व्यापक बनाने का जोखिम है। ये संस्थाएं संभावित रूप से छूट अधिसूचना के विभिन्न खंडों के तहत छूट का दावा कर सकती हैं, जिसमें "सरकारी प्राधिकरण" द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं शामिल हैं। "सरकारी प्राधिकरण" शब्द की एक उदार व्याख्या सरकारी खजाने पर अनुचित रूप से बोझ डाल सकती है। रिलायंस को आयुक्त में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया था।

सीमा शुल्क विभाग (आयात), मुंबई बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड

ओआरएस। 9 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी अधिसूचना या छूट प्रदान करने वाले खंड की व्याख्या राजस्व के पक्ष में किसी भी अस्पष्टता के समाधान के साथ सख्ती से और शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए।

च) आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला केंद्रीय कानूनों, अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 ("1961 अधिनियम", इसके बाद) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 ("2007 अधिनियम", इसके बाद) के तहत निगमित संस्थान हैं, और वे संविधान की अनुसूची XII के समान किसी भी कर्तव्य या जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं; इसलिए, दोनों शैक्षणिक संस्थान "सरकारी प्राधिकरण" के वर्गीकरण के तहत नहीं आते हैं और न ही उन्हें नकारात्मक सूची के तहत छूट दी गई है।

5 (2009) 5 एस. सी. सी. 641

6 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1122 7 (2017) 12 एस. सी. सी. 1

8 (1961) 3 एस. सी. आर. 386 9 (2018) 9 एस. सी. सी. 433

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 434

छ) एस. पी. सी. एल. ने स्व-मूल्यांकन के माध्यम से सेवा कर का भुगतान किया है। रिलायंस था आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

कोलकाता 10 इस तर्क के समर्थन में कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत एक मूल्यांकन आदेश होने के नाते स्व-मूल्यांकन का आदेश अपील योग्य है और धनवापसी का दावा तब तक टिकाऊ नहीं है जब तक कि मूल्यांकन को अलग नहीं किया जाता है।

ज) आई. आई. टी. पटना के "सरकारी प्राधिकरण" के रूप में वर्गीकरण का एस. पी. सी. एल. और एन. बी. सी. सी. के बीच लेनदेन पर सेवा कर के लागू होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। तर्क का सार इस मामले की विशिष्ट सी प्रकृति में निहित है: एस. पी. सी. एल. ने अपनी सेवाएं एन. बी. सी. सी. को दी हैं, न कि सीधे आई. आई. टी. पटना को। आई. आई. टी. पटना ने एन. बी. सी. सी. को एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिससे एस. पी. सी. एल. इस विशेष लेनदेन में सेवा प्रदाता और एन. बी. सी. सी. सेवा प्राप्तकर्ता बन गया है। नतीजतन, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एस. पी. सी. एल. ने सीधे आई. आई. टी. पटना को सेवाएं प्रदान कीं। एनबीसीसी के पास छूट अधिसूचना के तहत "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" का दर्जा नहीं है, और इसने इस तरह के दावे पर जोर नहीं दिया है। इसलिए, एस. पी. सी. एल. और एन. बी. सी. सी. के बीच गतिविधियाँ और लेनदेन सेवा कर के अधीन हैं और छूट अधिसूचना के तहत छूट के लिए योग्य नहीं हैं।

12. एस. पी. सी. एल. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने पटना उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि जबकि निर्माण सेवाओं को 1994

के अधिनियम की धारा 65 के तहत कर योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, छूट अधिसूचना सरकार, स्थानीय अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए छूट प्रदान करती है।आई. आई. टी. पटना, राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में, संसद द्वारा 1961 के अधिनियम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत स्थापित किया गया था। इसी तरह एन. आई. टी. राउरकेला की स्थापना 2007 के अधिनियम के तहत की गई थी। नतीजतन, आई. आई. टी. पटना और एन. आई. टी. राउरकेला को छूट अधिसूचना के खंड 2 (ओं) (i) के अनुसार सरकारी प्राधिकरण माना जाना चाहिए, जिसे स्पष्टीकरण अधिसूचना के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।अपीलार्थियों के इस निवेदन के जवाब में कि आई. आई. टी. पटना के "सरकारी प्राधिकरण" के रूप में वर्गीकरण का सेवा कर की प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा -

10 (2019) 17 एससीसी 46

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एस. पी. सी. एल. और एन. बी. सी. सी. के बीच क्रमशः सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में लेन-देन, विद्वान वकील ने छूट अधिसूचना के खंड 29 (एच) से समर्थन प्राप्त किया, जो उप-ठेकेदारों द्वारा कार्य अनुबंध के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को किसी अन्य ठेकेदार को कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करने से छूट देता है, जिन्हें पहले से ही छूट अधिसूचना के तहत छूट दी गई है।तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं थी और वे पूरी तरह से खारिज किए जाने के योग्य थे।

13. आई. आई. टी. पटना की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने पटना उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया।उनके अनुसार, आई. आई. टी. पटना ने स्पष्टीकरण अधिसूचना द्वारा संशोधित छूट अधिसूचना के तहत "सरकारी प्राधिकरण" के रूप में अर्हता प्राप्त की है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खंड 2 (ओं) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निहित प्रावधान स्वतंत्र असंवैधानिक प्रावधान हैं और "इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी" अभिव्यक्ति केवल उपखंड (ii) से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण को सेवा कर से छूट प्राप्त करने के लिए 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी होनी चाहिए।संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरण इस शर्त के अधीन नहीं है।हस्तक्षेप के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है, वकील ने सीए-आई को बर्खास्त करने का अनुरोध किया।

विश्लेषण

14. अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले, प्रशंसा की सुविधा के लिए छूट अधिसूचना और स्पष्टीकरण अधिसूचना से संबंधित खंडों को जोड़ना उचित होगा:

छूट सूचना	स्पष्टीकरण सूचना
2("सरकारी प्राधिकारी" से कोई बोर्ड, या प्राधिकरण या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है;	2("सरकारी प्राधिकरण" से कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है; (i) संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित; या (ii) संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ सरकार द्वारा स्थापित;

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 436

435

15. पहली और सबसे महत्वपूर्ण दो परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, स्पष्टीकरण अधिसूचना के पीछे के उद्देश्य का पता लगाना आवश्यक है, जिसने छूट अधिसूचना में संशोधन किया और "सरकारी प्राधिकरण" को फिर से परिभाषित किया। छूट अधिसूचना के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इसमें छूट केवल उन संस्थाओं को दी गई थी, अर्थात् बोर्ड या प्राधिकरण या निकाय, जो तीन आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात्: क) सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किया गया हो, ख) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित, और ग) संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करना। यह स्पष्ट है कि छूट का दायरा केवल कुछ संस्थाओं तक ही सीमित था। हालाँकि अपीलकर्ताओं द्वारा "सरकारी प्राधिकरण" को फिर से परिभाषित करने का कारण उपलब्ध नहीं कराया गया है, हम मानते हैं कि "सरकारी प्राधिकरण" की प्रतिबंधित अवज्ञा के कारण छूट देने के लिए योजना की अक्षमता इसके लिए ट्रिगर थी और इसलिए, छूट का दायरा "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा का जवाब देने वाली संस्थाओं के एक बड़े वर्ग को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। इसलिए स्पष्टीकरण अधिसूचना के माध्यम से एक

संशोधन पेश किया गया, जिसने "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा का विस्तार किया और संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी के साथ स्थापित किए जाने की शर्त के बिना संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय को भी सेवा कर के लिए छूट आधार का विस्तार किया।

16. जबकि संशोधित खंड 2 (ओं) की उपरोक्त व्याख्या को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अपीलकर्ताओं ने यह प्रस्तुत करते हुए इसका विरोध किया है कि खंड 2 (ओं) में "सरकारी प्राधिकरण" की संशोधित अवज्ञा की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि खंड 2 (ओं) के तहत लंबी पंक्ति को उपखंड (i) और उपखंड (ii) दोनों पर लागू किया जा सके। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थियों के अनुसार, खंड 2 (ओं) (i) के तहत "सरकारी प्राधिकरण" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, ऐसा प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय न केवल संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण होना चाहिए, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत एक नगरपालिका को सौंपे गए किसी भी समान कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से सरकार की 90 प्रतिशत या उससे अधिक भागीदारी भी होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

17. हमें अपीलार्थियों द्वारा दी गई बाद की व्याख्या से असहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

18. अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम। कलकत्ता निगम 11, इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने क्रेज़ ऑन स्टैच्यू लॉ (6 वीं संस्करण) पर भरोसा करते हुए कहा कि जहां किसी कानून की भाषा स्पष्ट है, शब्द अपने आप में सटीक और स्पष्ट हैं, और एक शाब्दिक पठन बेतुका निर्माण की ओर नहीं ले जाता है, व्याख्या के नियमों को लागू करने की आवश्यकता गायब हो जाती है और अपने लुप्त होने के बिंदु तक पहुंच जाती है।

19. भारत संघ और अन्य बनाम में यह न्यायालय।इंड-स्विफ्ट प्रयोगशालाएँ

लिमिटेड 12 ने अभिनिर्धारित किया कि किसी प्रावधान को सुसंगत निर्माण केवल तभी दिया जाना चाहिए जब वह अस्पष्टता में डूबा हो और स्पष्टता का अभाव हो, न कि जब वह स्पष्ट रूप से स्पष्ट और स्पष्ट हो।

20. विचाराधीन प्रावधान के खाली पढ़ने से जो स्पष्ट और अस्पष्ट है, उसकी व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जैसे इसे निर्धारित किया गया है, न कि इस तरह से कि यह अवज्ञापूर्ण है और प्रावधान के अर्थ और संदर्भ को मौलिक रूप से बदल देता है। बिक्री आयुक्त के मामले में इस न्यायालय की एक निर्णायक पीठ के फैसले में यह विचार व्यक्त किया गया है।

कर, यू. पी. बनाममोदी शुगर मिल्स लिमिटेड 13.वहाँ से प्रासंगिक मार्ग

यह नीचे लिखा है:“10. [...] एक कर कानून की व्याख्या करने में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से अनुचित हैं। न ही कर लगाने वाले कानूनों की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणाओं पर की जा सकती है। न्यायालय को कानून के शब्दों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। इसे एक कर कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आलोक में करनी चाहिए: यह ऐसी किसी भी चीज़ का संकेत नहीं दे सकता है जो व्यक्त नहीं की गई है; यह कानूनों में प्रावधानों का आयात नहीं कर सकता है ताकि किसी भी कल्पित अवज्ञा की आपूर्ति की जा सके।”

21. यह वैधानिक व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी प्राधिकरण, जिसे कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है, किसी उद्देश्य के लिए कानून बनाता है; इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि वह इसमें शामिल नहीं होगा।

11 (1967) 2 एससीआर 170 12 (2011) 4 एससीसी 635 13 (1961) 2 एससीआर 189 437

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 438

अनावश्यक या व्यर्थ कानून। यह न्यायालय, उत्कल ठेकेदारों और

जॉइनरी (पी) लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 14, ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझाया:

“9. [...] यह फिर से याद रखना महत्वपूर्ण है कि संसद अनावश्यक रूप से अपनी सांसों बर्बाद नहीं करती है। जिस तरह संसद से अनावश्यक अभिव्यक्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, उसी तरह संसद से भी अनावश्यक रूप से खुद को व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। भले ही संसद बिना किसी अर्थ के किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन संसद वहां कानून नहीं बनाती है जहां किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। संसद को कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है और न ही इसे निरर्थक कानून बनाने के लिए माना जा सकता है। संसद केवल यह बताने के लिए कानून नहीं बनाती है कि क्या कहना अनावश्यक है या वह करना जो पहले से ही वैध रूप से किया गया है। संसद को अनावश्यक रूप से कानून बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है।”

22. कानूनों की व्याख्या के कुछ उदाहरणों पर ध्यान देने के बाद, अब हम थोड़े से अंग्रेजी व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। शब्द "या" के साथ-साथ शब्द "और" एक संयोजन है और यह सर्वविदित है कि शब्दों, वाक्यांशों या खंडों को जोड़ने के लिए एक संयोजन का उपयोग किया जाता है। "या" और "और" संयोजनों को कैसे पढ़ा जाए, इस पर आधिकारिक ग्रंथों और न्यायिक निर्णयों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के अनुसार

सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, "या" शब्द आम तौर पर असंगत होता है।

जबकि "और" शब्द आम तौर पर संयोजी होता है। अंग्रेजी कानून में, स्थिति क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट है, जैसा कि लॉर्ड स्कूटन ने ग्रीन बनाम प्रीमियर ग्लिनहोनवी स्लेट कं. 15 में समझाया है, कि कोई

भी कानून में "या" के रूप में "और" को तब तक नहीं पढ़ता जब तक कि कोई बाध्य न हो, क्योंकि "या" का आम तौर पर अर्थ नहीं है "और" और "और" का आम तौर पर अर्थ नहीं है "या"।

23. जब विचाराधीन प्रावधान का अर्थ खंड 2 (ओं) में "या" के उपयोग से स्पष्ट और स्पष्ट होता है, तो सुश्री बागची के प्रस्तुत करने में कोई बल नहीं रहता है कि "या" की व्याख्या "और" के रूप में की जानी चाहिए। हमारी राय में, खंड 2 (ओं) में प्रयुक्त "या" शब्द एक विकल्प निर्धारित करने के विधायी इरादे को प्रकट करता है। व्याख्या के सुनहरे नियम के अनुसार कि शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, खंड 2 (ओं) में "या" शब्द का उपयोग हमें स्पष्ट रूप से सामान्य और सामान्य अर्थ को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया प्रतीत होता है, जो एक विकल्प को दर्शाने के लिए है।

14 (1987) 3 एससीसी 279

15 (1928) 1 के. बी. 561, पृष्ठ 569

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एक विकल्प देना; और, हम इसे एक अलग अर्थ नहीं दे सकते जब तक कि यह अस्पष्टता की ओर न ले जाए या खंड 2 (ओं) को पूरी तरह से अव्यवहारिक न बना दे। श्री जयराम एजुकेशनल ट्रस्ट में इस न्यायालय के फैसले से हम अपने विचार में दृढ़ हैं।

बनाम ए. जी. सैयद मोहिदीन 16, जहाँ यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

“11. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी कानून के प्रावधान को किसी भी शब्द को जोड़े, प्रतिस्थापित या छोड़े बिना, स्वाभाविक तरीके से, सादा और सीधा पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा करते समय, प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उनका प्राकृतिक, सामान्य या लोकप्रिय अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए। केवल तभी जब इस तरह के सादे और सीधे पढ़ने, या इस तरह के पढ़ने पर शब्दों को स्वाभाविक और सामान्य अर्थ बताते हुए, अस्पष्टता, अस्पष्टता, अनिश्चितता या बेतुकेपन की ओर ले जाता है जो स्पष्ट रूप से विधायिका या विधायक द्वारा अभिप्रेत नहीं थे, तो अदालत को प्रावधान के सही अर्थ पर पहुंचने के लिए निर्माण और व्याख्या के तय नियमों वाली अपनी व्याख्या टूलकिट खोलनी चाहिए। व्याख्या के साधनों का उपयोग करते समय, अदालत को याद रखना चाहिए कि यह कानून का लेखक नहीं है जिसे संरचना और सामग्री को बदलने के लिए संशोधन, प्रतिस्थापन या हटाने का अधिकार है। एक दुभाषिया के रूप में अदालत कानून में बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है। यह केवल प्रावधान की व्याख्या कर सकता है, ताकि इसे सार्थक और व्यवहार्य बनाया जा सके ताकि विधायी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, जब अस्पष्टता, अस्पष्टता या बेतुका हो। व्याख्या का उद्देश्य एक प्रावधान बनाना नहीं है जो न्यायाधीश को लगता है कि यह होना चाहिए, बल्कि इसे वही बनाना है जो विधायिका का इरादा था।”

24. वर्तमान मामले में, उपखंड (i) और (ii) के बीच "या" शब्द उपखंड (i) की स्वतंत्र और असंगत प्रकृति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि उपखंड (i) के बाद उपयोग किए गए "या" की व्याख्या "और" के रूप में नहीं की जा सकती है ताकि इसे खंड 2 (ओं) की लंबी पंक्ति में उल्लिखित शर्त के साथ जोड़ा जा सके जो केवल उपखंड (ii) पर लागू होती है।

25. एक अलग दृष्टिकोण को लागू करते हुए, आइए हम खंड 2 (ओं) में विराम चिह्नों के आलोक में सुश्री बागची के प्रस्तुत करने के मूल्य का परीक्षण करें। यह कांतारू राजीवरु में इस न्यायालय के नौ माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा आयोजित किया गया है।

बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। 17 कि जब कोई प्रावधान है

16 (2010) 2 एस. सी. सी. 513

17 (2020) 9 एससीसी 121, पैरा 18।

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 440

439

सावधानीपूर्वक विराम चिह्न और इसके अर्थ के बारे में संदेह है, निस्संदेह विराम चिह्न को महत्व दिया जाना चाहिए; हालाँकि, कुछ मामलों में विराम चिह्न के अपने उपयोग हो सकते हैं, लेकिन इसे निश्चित रूप से एक नियंत्रक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे सादे अर्थ को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह का अवलोकन करते हुए, इस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान में कई फैसलों के साथ-साथ विराम चिह्न अल्पविराम पर भी विचार किया।

26. इसके बाद यह है कि निर्माण के उद्देश्य से विराम चिह्न, हालांकि एक मामूली तत्व है, का सहारा लिया जा सकता है।

27. वर्तमान मामले में, अर्धविराम का उपयोग कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसे उपखंड (ii) से अलग करने के स्पष्ट इरादे के साथ जानबूझकर शामिल करना है। इसके अलावा, खंड 2 (ओं) के एक सादे और शाब्दिक पठन पर यह देखा जा सकता है कि उपखंड (i) के बाद एक अर्धविराम है, उपखंड (ii) अल्पविराम के साथ समाप्त होता है। यह अनिवार्य रूप से एकमात्र संभावित निर्माण का समर्थन करता है कि उपखंड (ii) के बाद अल्पविराम का उपयोग इसे उसके बाद प्रदान की गई लंबी रेखा से संबंधित करता है और कल्पना के किसी भी विस्तार से, लंबी रेखा के अनुप्रयोग को उपखंड (i) तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका दायाँ अर्धविराम के साथ समाप्त होता है। इसलिए, हमारी राय है कि खंड 2 (ओं) की लंबी पंक्ति केवल उप-खंड (ii) को नियंत्रित करती है न कि उप-खंड (i) को इस सरल कारण से कि उप-खंड (i) के बाद अर्धविराम की शुरुआत के बाद "या" शब्द ने इसे एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में स्थापित किया है, जिससे यह उप-खंड (ii) से अलग हो गया है। यदि लेखक चाहता था कि इन दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाए, तो इसका कोई प्रशंसनीय कारण नहीं है कि उसने विराम चिह्न अर्धविराम के बिना "और" शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। जबकि स्पष्टीकरण अधिसूचना ने खंड 2 (ओं) का एक संशोधित संस्करण पेश किया, लेखक के लिए

"सरकारी प्राधिकरण" की अवहेलना करने के लिए पूरा कैनवास खुला था, जो भी वह चाहे; हालाँकि, "सरकारी प्राधिकरण" को खंड को पहले की परिभाषा के विपरीत व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से फिर से परिभाषित किया गया था। इसलिए, हम "या" के रूप में "और" की व्याख्या नहीं कर सकते हैं ताकि खंड 2 (ओं) में उल्लिखित विकल्प गायब हो जाए।

28. आइए हम समस्या पर एक अलग कोण से विचार करें। "सरकारी प्राधिकरण" की संशोधित परिभाषा और परिभाषा में कुछ विराम चिह्न (दो अर्धविराम और दो अल्पविराम) और संयोजन 'या' को ऊपर देखा गया है। शाब्दिक रूप से पढ़े जाने पर, उपखंड (i) और (ii) के बीच 'या' का संयोजन स्पष्ट रूप से दोनों खंडों को पहले खंड के साथ दो भागों में विभाजित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

भाग दूसरे भाग से पूरी तरह से स्वतंत्र है। पहला भाग अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम है। एक विसंगत परिणाम की ओर ले जाने वाले निर्माण से बचना होगा और इससे बचने के लिए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि खंड 2 (ओं) की लंबी पंक्ति जो "90 प्रतिशत" से शुरू होती है और "संविधान" के साथ समाप्त होती है, वह उपखंड (ii) के योग्य है; और, यदि 'या' को 'और' के रूप में पढ़ा जाना है, जिसका अर्थ है कि "90 प्रतिशत के साथ भाग. संविधान" को उपखंड (i) और (ii) दोनों के योग्य होने के रूप में पढ़ा जाना है, तो "सरकारी प्राधिकरण" को फिर से परिभाषित करने का इरादा निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, जिस उद्देश्य के लिए "सरकारी प्राधिकरण" को फिर से परिभाषित किया गया था, वह निश्चित रूप से इसे व्यवहार्य बनाना था। इसलिए, हम ऐसे निर्माण का सहारा नहीं ले सकते हैं जो अव्यवहार्यता कारक के निर्वाह की अनुमति देगा। यह मानते हुए कि सुश्री बागची ने जो तर्क दिया वह सही है, अपीलकर्ताओं के लिए यह दायित्व था कि वे हमारे ध्यान में लाएं, यदि अभिवचन के माध्यम से नहीं, लेकिन कम से कम प्रासंगिक कानूनों के संदर्भ में, जो विशेष प्राधिकरणों/बोर्डों/निकायों में से कौन से कानून द्वारा बनाए गए हैं-केंद्र या राज्य-"सरकार द्वारा इक्विटी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ"। परिभाषा खंड के प्रत्येक शब्द को कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए और केवल इसलिए कि शैक्षणिक पहलुओं को बढ़ावा देना संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के संदर्भ में नगरपालिका के कार्यों में से एक है, जिसमें अनुसूची XII के साथ जोड़ा गया है, कोई वैध तर्क नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा समानता या नियंत्रण, 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित प्राधिकरण/बोर्ड/निकाय के अस्तित्व में नहीं दिखाया जाता है। संयोग से, न तो याचिका में कोई संकेत है और न ही सुश्री बागची ऐसे किसी प्राधिकरण/बोर्ड/अन्य निकाय की पहचान का खुलासा करने में सक्षम हैं जो उनके तर्क में शामिल है। स्पष्टीकरण अधिसूचना के खंड 2 (ओं) में "सरकारी प्राधिकरण" की अवज्ञा के उपरोक्त निर्माण के दायरे में आने वाला ऐसा कोई पहचान प्राधिकरण/बोर्ड/निकाय नहीं है, जिसे अपीलकर्ता हमसे स्वीकार करने की अपील करते हैं, हमारे संज्ञान में लाए जाने के बाद, हम पटना उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णयों में किसी भी तरह की गलती का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों को छूट अधिसूचना

का लाभ देते हैं, और एस. पी. सी. एल. को एक विशेषाधिकार देते हैं। 29. सुश्री बागची द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय से हमें मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के, प्रासंगिक खंड के निर्माण के प्रश्न पर, क्योंकि उन निर्णयों में से किसी में भी छूट अधिसूचना और स्पष्टीकरण अधिसूचना से उत्पन्न मुद्दे से निपटने का अवसर नहीं था, जिस पर हमें विचार करने का काम सौंपा गया है।

आयुक्त, ग्राहक केंद्रीय कर और सेवा कर, पटना बनाम एम/एस शापूरजी पालोनजी और कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. [दीपांकर दत्त, जे.] 442

441

30. सुश्री बागची ने दिलीप कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक उप-न्यायाधीश पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया कि छूट अधिसूचना की व्याख्या करने में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, राजस्व के पक्ष में व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए; साथ ही, छूट अधिसूचना की प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर यह दिखाने के लिए होगा कि उसका मामला छूट खंड या छूट अधिसूचना के मापदंडों के भीतर आता है। शुरुआत में, हम दर्ज करते हैं कि उसमें निर्धारित प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, हम दिलीप कुमार (उपरोक्त) के आधार पर सुश्री बागची के तर्क को अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह अनुपात इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। यह, सरल कारण से, कि जहाँ तक खंड 2 (ओं) की व्याख्या का संबंध है, कोई अस्पष्टता मौजूद नहीं है। हम अपनी राय में वर्बिस नुल्ला एस्ट में लैटिन मैक्सिम उद्धरणों द्वारा समर्थित हैं।

अम्बिगुइटास, इबी नुल्ला एक्सपोजिशियो कॉन्ट्रा वर्बा एक्सप्रेससा फाई एंडा एस्ट, जिसका अर्थ है कि जब शब्दों में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो शब्दों के विपरीत कोई व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इसलिए, यह एक धूप वाले दिन के रूप में स्पष्ट है कि खंड 2 (ओं) का केवल एक ही प्रशंसनीय निर्माण होता है जिसे पटना उच्च न्यायालय ने अपनाया है, और जिसे हम बरकरार रखने के लिए इच्छुक हैं।

31. सुश्री बागची ने कहा था कि विवादित निर्णय बड़ी संख्या में वैधानिक निकायों को शामिल करने के लिए छूट के दायरे को व्यापक बनाता है, इसलिए सरकारी खजाने पर अनुचित रूप से बोझ डालता है। हम देखते हैं कि अधिसूचना जारी करने की क्षमता रखने वाले प्राधिकरण ने "सरकारी प्राधिकरण" की पुनः अवहेलना करके अपना काम पूरा किया और अब यह कार्य अदालतों को सौंपा गया है कि वे कानून की व्याख्या करें। इस मोड़ पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो माननीय ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.

गिरधारी लाल एंड संस बनाम बलराम नाथ माथुर 18. कानून की स्थिति थी

निम्नलिखित शब्दों में एफ़ाई आरमेडः “6. जहां शब्दों पर अलग-अलग व्याख्याएं किए जाने की संभावना है और एक सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ शब्दों का उपयोग करता है तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसे खुद को समझाने के लिए कहा जा सकता है और वह ऐसा कर सकता है और कह सकता है कि उसका मतलब एक बात है न कि दूसरी। लेकिन अगर यह

विधायिका है जिसने कानून बनाकर खुद को व्यक्त किया है और विधायिका ने जो कहा है उसकी व्याख्या करने में मतभेद पैदा होते हैं, तो एक विधायिका को उन मतभेदों को हल करने के लिए बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता है। विधायिकाएँ, व्यक्तियों के विपरीत,

18 (1986) 2 एस. सी. 237

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जितनी बार व्याख्या की अलग-अलग परंपराएँ उत्पन्न होती हैं, उतनी बार खुद को समझाने के लिए आगे नहीं आ सकते। इसलिए विधायिका का क्या अर्थ है, यह स्पष्ट करके कानूनों की व्याख्या करने का कार्य अदालतों को आवंटित किया जाता है। बेशक, जहां शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहां निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। इस तरह के शब्द आमतौर पर अपने लिए बोलते हैं। चूंकि इन शब्दों ने विधायिकाओं के लिए और न्यायाधीशों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात की होगी, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि विधायिका का इरादा वही था जो शब्द स्पष्ट रूप से कहते हैं। यह निर्माण के तथाकथित सुनहरे नियम का वास्तविक आधार है कि जहां विधियों के शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, उन्हें प्रभाव दिया जाना चाहिए। अदालत को सादे शब्दों को प्रभावी बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ऐसे शब्दों की सरलता में कोई आकर्षण या जादू है, बल्कि इसलिए कि सादे शब्दों से विधायिका के इरादे को दूसरों के साथ-साथ न्यायाधीशों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की उम्मीद की जा सकती है।”

32. उपर्युक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इसके संचालन के विस्तारित दायरे के परिणामस्वरूप प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या अपने आप में प्रावधान की अस्पष्टता को जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

33. व्याख्यात्मक साधनों का उपयोग करके एक कानून को व्यवहार्य बनाना और एक प्रकार के न्यायिक विधान में उद्यम करना दो अलग-अलग चीजें हैं। केवल इसलिए कि कानून इच्छित या वांछित परिणाम नहीं देता है, यह हमारे लिए लक्ष्मण रेखा को पार करने और उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए व्याख्या के साधनों का उपयोग करने का कारण नहीं हो सकता है। किसी कानून को व्यवहार्य बनाने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए न कि किसी विशेष परिणाम तक पहुंचने के लिए।

निष्कर्ष

34. उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। विवादित निर्णयों और आदेशों को बरकरार रखा जाता है और बिना किसी खर्च के आदेश के अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

